

3

उपायुक्त का न्यायालय, दुमका

आर०एम०आर० सं०- 06/2013-14

विशेश्वर महतो आवेदक
बनाम
किशन महतो एवं अन्य विपक्षी

॥ आदेश ॥

06/05/2016

यह रे०मि० रिविजन वाद सं० 06/2013-14 विशेश्वर महतो बनाम किशन महतो एवं अन्य, मौजा महारो, अंचल जामा के बीच अनुमंडल पदाधिकारी दुमका के आर०ई० वाद सं० 24/2003-04 में पारित आदेश दिनांक 20.09.2010 के विरुद्ध दायर किया गया है।

मैंने आवेदक के विद्वान अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख में उपलब्ध कागजातों का अवलोकन किया।

विपक्षी की ओर से दिनांक 06.05.2016 को लिखित बहस दाखिल किया गया।

अभिलेख में उपलब्ध कागजातों के आवलोकन से स्पष्ट होता है कि मौजा महारो के जमाबन्दी नं० 62 दाग सं० 347 गत सर्वे सेटलमेंट में खेलु महतो, दालु महतो एवं मुकु महतो के नाम से संयुक्त रूप से दर्ज है। विपक्षीगण जमाबन्दी रैयत के वंशज है। उनके द्वारा निम्न न्यायालय में विपक्षी को मौजा महारो के दाग सं० 347 के अतिक्रमित भूमि से उच्छेदित करने हेतु आवेदन दाखिल किया गया। इसपर अंचल अधिकारी से जांच प्रतिवेदन की मांग की गई एवं विपक्षी से कारण पृच्छा की मांग की गई। किन्तु उनके ओर से कोई कारण पृच्छा दाखिल नहीं किया गया है।

निम्न न्यायालय में उपलब्ध अंचल अधिकारी द्वारा समर्पित प्रतिवेदन में उल्लेख है कि प्रश्नगत दाग के मकान में निवास करते हैं। मकान करीब तीस वर्षों से अधिक का है। आवेदक को प्रश्नगत जमीन किस प्रकार प्राप्त हुआ है, कोई ठोस प्रमाण नहीं दिखलाया गया है किन्तु उन्हें महारो के प्रधान द्वारा मार्फती लगान रसीद कुछ वर्षों का निर्गत है। किन्तु निम्न न्यायालय द्वारा प्रश्नगत जमीन पर आवेदक का अवैध दखल मानते हुए उन्हें उक्त जमीन से उच्छेदित किया गया है।

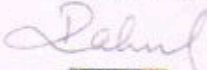
इस पर आवेदक का कहना है कि उनका दखल प्रश्नगत जमीन पर तीस वर्षों से है एवं मकान बनाकर निवास कर रहे हैं। उन्हें मकान से उच्छेदित नहीं किया जा सकता है। अतः निम्न न्यायालय का आदेश गलत है।


विपक्षी द्वारा दाखिल लिखित बहस में उल्लेख किया गया है कि आवेदक उक्त जमीन से कोई संबंध नहीं रखता है तथा इस पर उनका कोई दावा नहीं बनता है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश सही है।

B

उपरोक्त वर्णित तथ्यों से स्पष्ट होता है कि प्रश्नगत जमीन विपक्षियों का जमाबन्दी जमीन है एवं सं0प0 काश्तकारी अधिनियम के अनुसार अहस्तान्तरणीय है। आवेदक किस आधार पर प्राप्त किया है, प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख नहीं है। साथ ही मौजा के प्रधान द्वारा भी मार्फती लगान रसीद निर्गत किया गया है, का भी कोई स्पष्ट आधार का उल्लेख नहीं है। आवेदक द्वारा भी कोई कागजात अपने दावों के समर्थन में दाखिल नहीं किया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि आवेदक का प्रश्नगत जमीन में अवैध दखल है। अतः निम्न न्यायालय द्वारा पारित आदेश को बरकरार रखते हुए आवेदक के आवेदन को अस्वीकृत किया जाता है।

लेखापित एवं संशोधित ।


उपायुक्त
दुमका।


उपायुक्त
दुमका।

251 Dabul- 25/6/16.

NOTO